4 dna JAIPUR, SATURDAY 20.06.2015

Renewable energy is the future: Experts

dna correspondent @jaipurdna

CUTS International and Friedrich Ebert Stiftung, India in joint association with the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (RERC) organised a seminar on Friday, to discuss country's energy transformations.

The seminar covered the topic on 'Green Growth and Energy Security in India: Political Economy of Transformation and Challenges.'

Vishvanath Hiremath, chairman of Rajasthan Electricity Regulatory Commission, said, "Tomorrow renewable energy has to replace the conventional power for the betterment of the society. Consumer education and awareness will be crucial for this change." In a bid to motivate consumer education and awareness, RERC earmarked a budget of Rs 50 lakh per Discom in its recent tariff order. It also sought CUTS' input for improving consumer awareness and education in the state.

POWER TALK

Pradeep S Mehta, secretary general, CUTS International, initiated the seminar by raising concern over the challenges faced by India, in respect to the gap in the demand and supply of power generation. He argued that this can be curtailed only by apt power generation backbone and revolutionising power generation bases with a major share of renewables, simultaneously.

राजस्थान पत्रिका जयपुर . शनिवार . 20.06.2015

बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक होना होगा

कट्स इंटरनेशनल की संगोष्ठी में विनियामक आयोग के चेयरमैन बोले

जयपुर @ पत्रिका

patrika.com/city

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन विश्वनाथ हीरामथ का मानना है कि देश हो या प्रदेश, बिजली का क्षेत्र काफी चुनौतिपूर्ण है। सभी चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन तकनीकी सुधार व उपभोक्ताओं को जागरूक कर इस पर जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि इस बात को ध्यान में रखकर आयोग ने इस बार बिजली कम्पनियों के टैरिफ आदेश में न सिर्फ उपभोक्ता जागरूकता का जिक्र किया है, बल्कि इसके लिए 50-50 लाख रुपए का अलग से प्रावधान भी किया है।

हीरामथ शुक्रवार को ग्रीन ग्रोथ एवं एनजी सिक्योरिटी इन इंडियाः पोलिटिकल इकोनोमी ट्रांसफोरमेशन एण्ड चैलेन्जेस विषयक संगोष्ठी में बोल रहे थे। कट्स इंटरनेशनल व जर्मन संस्था एफईएस इंडिया की ओर से आयोजित संगोष्ठी में हीरामथ ने कहा कि आने वाला कल पारम्परिक ऊर्जा के बजाय अक्षय ऊर्जा का होगा। इसके लिए आमजन को भी तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम में कट्स महामंत्री प्रदीप एस मेहता ने अक्षय ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच के अन्तर को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। जर्मन संस्था के प्रतिनिधि मार्क सेक्सर ने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन पर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चाएं हो चुकी है, जिसमें अक्षय ऊर्जा की संभावित भूमिका तेजी से उभर कर सामने आई है। ऐसे में जरूरी है कि अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए कदम बढ़ाए जाए। संगोष्ठी में विद्युत क्षेत्र के कई विशेषज्ञों ने भी विचार व्यक्त किए।

दैनिक नवज्योति जयपुर, शनिवार, 20 जून 2015

आने वाला कल अक्षय ऊर्जा का

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर

आने वाला कल समाज के हित के लिए पारम्परिक ऊर्जा के स्थान पर अक्षय ऊर्जा का होगा। इस परिवर्तन में उपभोक्ता शिक्षा व जागरूकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह कहना है राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष विश्वनाथ हीरामथ का। वे शुक्रवार को 'कट्स' व जर्मन संस्था एफईएस, इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में 'ग्रीन ग्रोथ एवं एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडियाः पॉलिटिकल इकोनोमी ट्रांसफोरमेशन एण्ड चैलेन्जेस' विषय पर एसएमएस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने विद्युत सेवा तंत्र के विभिन्न खण्डों में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये सभी चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन ऐसी नहीं हैं, जिनको जीता नहीं जा सकें।

जहां तक ढांचागत चुनौतियों का प्रश्न है, इनको तकनीकी सुधारों द्वारा काबू में किया जा सकता है, लेकिन चूंकि विद्युत क्षेत्र आने वाले दिनों में और अधिक जटिल होता जा रहा है। इसलिए उपभोक्ता शिक्षा व जागरूकता और उपभोक्ताओं की सक्रिय भूमिका होनी जरूरी है। इस मौके पर 'कट्स' महामंत्री प्रदीप एस. महता और मार्क सेक्सर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने विचार व्यक्त किए।

दैनिक भास्कर

जयपुर, शनिवार 20 जून, 2015

अब पारंपरिक ऊर्जा के स्थान पर अक्षय ऊर्जा जरूरी

जयपुर| अब पारंपरिक ऊर्जा से स्थान पर अक्षय ऊर्जा जरूरी होगी। इसके लिए उपभोक्ता शिक्षा व जागरूकता जरुरी है। आरईआरसी की ओर से जारी टैरिफ आदेश में भी उपभोक्ता शिक्षा व जागरूकता के लिए हर डिस्कॉम को 50 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) के अध्यक्ष विश्वनाथ हीरामथ शुक्रवार को एक सेमीनार में मुख्य अतिथि के रुप में बोलते हुए यह कहा। कट्स व एफईएस इंजीनियर की ओर से आयोजित ग्रीन ग्रोथ एंड एनर्जी सिक्योरिटी इन इंजीनियर : पॉलिटिकल इकॉनामी ट्रांसफोरमेशन एंड चैलेंजेस विषय सेमीनार आयोजित किया गया था।